



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 864]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 18, 2017/आश्विन 26, 1939

No. 864]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017/ASVINA 26, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2017

सं. 51/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि.1314(अ).—**जबकि कि नामित प्राधिकारी ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं.15/17/2015-डीजीएडी, दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 के अंतर्गत रूस और तुर्की (जिन्हें एतश्मिन पश्चात विषयगत देश के रूप में संदर्भित किया गया है) से मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “सोडा ऐश” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु के रूप में संबोधित किया गया) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 2836 20 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर लगने वाले परिपाटन शुल्क को बनाए रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, की धारा 9क की उपधारा (5) के संबंध में, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 18 अप्रैल, 2013 को सा.का.नि. सं. 258 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं. 08/2013-सीमा शुल्क (एडीडी) के अंतर्गत लागू किया गया था, की मध्यावधि समीक्षा प्रारंभ की थी।

और जबकि विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की मध्यावधि समीक्षा के मामले में पद नामित पदाधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, में दिनांक 23 सितम्बर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/17/2015-डीजीएसी दिनांक 23 सितम्बर, 2016 में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

- तथापि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटन जारी है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन जांच की अवधि (इसके पश्चात् जिसे पीओआई के रूप में संबोधित किया गया है) के दौरान धनात्मक है, इसलिए घरेलू उद्योग की मात्रा, कीमतों और लाभ प्रदाता पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पीओआई के दौरान एवं पीओआई के पश्चात नहीं है।
- अंडरकटिंग एवं अंडरसेलिंग दोनों पीओआई तथा पीओआई के पश्चात ऋणात्मक हैं।
- पीओआई के दौरान तथा पीओआई के पश्चात क्षति मार्जिन ऋणात्मक है।

- iv. पीओआई के दौरान संबद्ध देशों द्वारा अन्य देशों के निर्यात की आधार कीमतों पर संभावित क्षति मार्जिन भी ऋणात्मक है।
- v. कीमत में वृद्धि और कीमत में कमी का प्रभाव नहीं है।
- vi. घरेलू उद्योग के लगभग सभी मात्रा प्राचल और कीमत प्राचल पीओआई के दौरान तथा पीओआई के पश्चात धनात्मक है और घरेलू उद्योग के निष्पादन में लंबी अवधि के लिए उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- vii. तथापि पाटन करने वाले देश, न तो घरेलू उद्योग क्षति का कारण है और न ही पाटनरोधी शुल्क के निरसन की स्थिति में संभावित क्षति का कारण हैं।

और संबद्ध देशों के मूल की अथवा निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के निरसन की सिफारिश की है।

और जहां, उक्त 23 सितम्बर, 2016 के अंतिम निष्कर्षों को विशेष सिविल आवेदन 16426 और 16428 के तहत माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और न्यायालय ने अपने दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 के आदेश में यह कहा है कि यदि नामित प्राधिकारी के द्वारा दर्ज विवादित व अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में, केन्द्र सरकार प्रतिपाटन नियमावली के नियम 18 के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में कोई अधिसूचना प्रकाशित करती है तो वह इन याचिकाओं के अंतिम निपटान तक लागू नहीं होगी।

और जहां कि केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 08/2013 –सीमा शुल्क (एडीडी) , दिनांक 18 अप्रैल, 2013, जिसे सा.का.नि. 258 (अ) दिनांक 18 अप्रैल, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) प्रकाशित किया गया था, को अधिसूचना सं. 56/2016 –सीमा शुल्क(एडीडी), दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 जिसे सा.का.नि. 1164 (अ) के द्वारा निरसित कर दिया गया था और ऐसे निरसन करने वाली अधिसूचना को स्पेशल सिविल एप्लीकेशन में 16426 और 16428 में विशेष सिविल आवेदन में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश तक स्थगित रखा गया था।

और अतः माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात ने दिनांक 23 फरवरी, 2016 के अपने सामान्य निर्णय द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2016 के प्रकटन विवरणों को 23 सितम्बर, 2016 के अंतिम जांच परिणामों के साथ-साथ नियमावली के नियम 18 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई परवर्ती अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया था तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी की कार्यवाही को बहाल करने के साथ-साथ उन्हें यह भी निर्देश दिये थे कि वे संबद्ध सांविधिक प्रावधानों के समनुरूप और निर्णय में किए गए प्रेक्षणों के आलोक में नए प्रकटन विवरण जारी करें।

और अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 25 अप्रैल, 2017 को अन्य मौखिक सुनवाई आयोजित की थी और हितबद्ध पक्षकारों को अपने मौखिक विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया था। साथ ही हितबद्ध पक्षकारों को लिखित निवेदन प्रस्तुत करने और उसके बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उन पर अपने उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया गया था।

जहां कि नामित अधिकारी ने विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 08/2013 –सीमा शुल्क (एडीडी) , दिनांक 18 अप्रैल, 2013, के तहत सा.का.नि. 258(अ), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार और प्रतिपाटन शुल्क की नियमावली के नियम 23 के अनुपालन में, 22 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं.15/17/2015-डीजीएडी, दिनांक 22 जुलाई, 2017 में मध्यावधि समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों को जारी किया, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार संबद्ध देशों के मूल की अथवा निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के निरसन की सिफारिश की है।

और जहां, उक्त 22 जुलाई, 2017 के अंतिम निष्कर्षों को विशेष सिविल आवेदन, 2017 का 14202 के तहत माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और न्यायालय ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 2017 के आदेश में यह कहा है कि यदि नामित प्राधिकारी के द्वारा दर्ज विवादित व अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में, केन्द्र सरकार प्रतिपाटन नियमावली के नियम 18 के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में कोई अधिसूचना प्रकाशित करती है तो वह इन याचिकाओं के अंतिम निपटान तक लागू नहीं होगी।

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ (प्रतिपाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. 56/2016, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 के अधिग्रहण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा, वित्त मंत्रालय( राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2013-सीमा शुल्क(एडीडी), दिनांक 18 अप्रैल, 2013 जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खंड-3, उपखंड (i) में जिसे सा.का.नि. 258(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2013 को

प्रकाशित को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई और करने से लोप की गई बातों को छोड़कर, करती है और ऐसा निरसन 2017 के 14202 विशेष सिविल आवेदन में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश तक स्थगित रहेगा।

[फा.सं. 354/30/2013-टीआरयू (भाग-II)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव,

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2017

#### No. 51 /2017-Customs (ADD)

**G.S.R.1314(E).**—Whereas, the designated authority *vide* notification No.15/17/2015- DGAD, dated the 1st October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 1st October, 2015, had initiated Mid-Term Review investigation in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Anti-dumping Rules) in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Soda Ash (hereinafter referred to as the subject goods), falling under sub-heading 2836 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from, Turkey and Russia (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.08/2013-Customs (ADD), dated the 18th April, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.258(E), dated the 18th April, 2013;

And, whereas, the designated authority, in its final findings in Mid-Term Review (hereinafter referred to as the final findings) *vide* notification No.15/17/2015-DGAD, dated the 23rd September, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd September, 2016, has come to the conclusion that-

- (i) although dumping has continued despite the anti-dumping duties in force and the dumping of subject goods from the subject countries is positive during the Period of Investigation (hereinafter referred to as POI), the adverse impact of the same on the volume, prices and profitability of the domestic industry is absent during the POI as well as post-POI;
- (ii) both undercutting and underselling are negative during POI as well as post-POI;
- (iii) the injury margin is negative during POI as well as post-POI;
- (iv) the likely injury margin, on the basis prices of third country exports by the subject countries during the POI are also negative;
- (v) price suppression and price depression effects are absent;
- (vi) all most all volume parameters and price parameters of the domestic industry are positive during POI and post-POI and there is a remarkable improvement of lasting nature in the performance of the domestic industry;
- (vii) although dumping continues, neither it has caused injury to the domestic industry, nor is there any likelihood of causing injury in the event of revocation of the anti-dumping duties,

and has recommended revocation of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries;

And whereas, the said final findings dated the 23rd September, 2016 were challenged in the Hon'ble High Court of Gujarat in Special Civil Applications No.16426 of 2016 and 16428 of 2016 and the High Court *vide* its order dated the 13th December, 2016 had held that in case, pursuant to the impugned final findings recorded by the designated authority, the Central Government published a notification in the Official Gazette under rule 18 of the Anti-dumping Rules, the same shall not be acted upon till the final disposal of these petitions;

And whereas, the Central Government had rescinded the notification of Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.08/2013-Customs (ADD), dated the 18th April, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.258(E), dated the 18th April, 2013, *vide* notification No.56/2016-Customs (ADD), dated 21st December 2016, published in the Gazette of India,

Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1164(E), dated the 21st December, 2016 and the operation of such rescission was kept in abeyance subject to the final order of the Hon'ble Court of Gujarat in Special Civil Applications No. 16426 of 2016 and 16428 of 2016;

And whereas Hon'ble Gujarat High Court *vide* its common judgment dated the 23rd February, 2017, quashed the disclosure statements dated the 14th September, 2016, final findings dated 23rd September, 2016, as well as subsequent notifications issued by the Central Government under rule 18 of the rules and restored the proceedings to the designated authority, directing the Designated Authority to issue fresh disclosure statement, in consonance with the relevant statutory provisions and in the light of the observations made in the judgment;

And whereas the Designated Authority conducted another oral hearing on 25th April, 2017, giving opportunity to the interested parties to present their views orally and the interested parties were allowed opportunity to file written submissions and thereafter rejoinder to the submissions made by other interested parties;

And whereas, the designated authority *vide* notification No. 15/17/2015-DGAD, dated 22nd July 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 22nd July 2017, has issued mid-term review final findings in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the Anti-dumping Rules, in the matter of anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in, or exported from, the subject countries imposed *vide* the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.08/2013-Customs (ADD), dated the 18th April, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.258(E), dated the 18th April, 2013, and has recommended revocation of anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries;

And whereas, the said final findings dated the 22nd July, 2017 has been challenged in the Hon'ble High Court of Gujarat in Special Civil Applications No.14202 of 2017 and the High Court *vide* its order dated the 31st July, 2017 has held that in case, pursuant to the impugned final findings recorded by the designated authority, the Central Government publishes a notification in the Official Gazette under rule 18 of the Anti-dumping Rules, the same shall not be acted upon till the final disposal of these petitions.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and in view of the aforesaid order of the Hon'ble High Court of Gujarat dated the 31st July, 2017, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.08/2013-Customs (ADD), dated the 18th April, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.258(E), dated the 18th April, 2013, in supersession of notification No. 56/2016-Customs (ADD), dated the 21st December, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, and such rescission shall remain in abeyance subject to the final order of the Hon'ble High Court of Gujarat in Special Civil Applications No. 14202 of 2017.

[F.No 354/30/2013-TRU (Pt.-II)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.